



न्यूज़ ब्रीफ

विलक: भारत में ग्राहक आधार 1,000 को पार करने के लिए तैयार



ऑरलैंडो। कृत्रिम मेधा क्षेत्र के अग्रणी कंपनी विलक ने भारतीय बाजार में वृद्धि को लेकर आशान्वित होने का इजहार किया है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि विलक ने पिछले दो साल में अपने कारोबार को दोगुना किया है और ग्राहकों की संख्या अब 800 से भी ज्यादा हो गई है। उनके अनुसार इस साल कंपनी का ग्राहक आधार 1,000 को पार कर जाएगा। उन्होंने डेटा विश्लेषण और एआई रणनीति में भागीदारी के लिए कई छोटे और मझौले कारोबारों के साथ भविष्य की योजना की बात की। उन्होंने कहा कि विलक के भारतीय शाखा में मात्र एक्सपैशन हुई है और कर्मचारी संख्या में भी वृद्धि हुई है। कंपनी ने पिछले 16 माह में भारत में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर दी है और नियुक्तियों का कार्य जारी रहेगा। वे भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ने के संकेत का समर्थन करते हुए निवेश के साथ एक वीरवंशी किरदार बनाने का दावा कर रहे हैं। विलक ने हाल ही में भारत में एक बड़े निवेश के साथ डेटा सेंटर खोला है, जो भारतीय बाजार के लिए नई सेवाएं प्रदान करेगा। यह कॉन्फिगरेशन के साथ क्लाउड ढांचे को बढ़ाने और भारतीय बाजार के साथ प्रतिबद्धता को गहरा करने में मदद करेगा।

भारत के कोयले का आयात 2024-25 में घटकर 26.35 करोड़ टन रहा



नई दिल्ली। भारत में कोयले का आयात वित्त वर्ष 2024-25 में 1.7 प्रतिशत घटकर 26.35 करोड़ टन रहा है। इसके सम्बंधित पिछले वित्त वर्ष, 2023-24, में देश कोयले का 26.82 करोड़ टन आयात करता था। इस वर्ष गैर-कोकिंग कोयले का आयात 16.71 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की 17.59 करोड़ टन से कम है। कोकिंग कोयले का आयात 5.40 करोड़ टन है जो पिछले वर्ष की 5.72 करोड़ टन से कम है। एक ई-कॉमर्स मंच द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मार्च में कोयले का आयात 2.27 करोड़ टन रहा जो पिछले वर्ष की 2.39 करोड़ टन की मुकाबला है। मार्च में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 1.48 करोड़ टन है जो 2023-24 के समान महीने की 1.53 करोड़ टन का है। मार्च में कोकिंग कोयले का आयात 44.1 लाख टन है जो 2023-24 के समान महीने की 53.4 लाख टन से कम है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल कोयले उत्पादन एक अरब टन के आंकड़े को पार कर गया है। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में कोयले उत्पादन 104.75 करोड़ टन है, जो 2023-24 में 99.78 करोड़ टन का था। इस तरह वित्त वर्ष के दौरान कोयले का उत्पादन 4.99 प्रतिशत बढ़ गया है।

बीते वित्त वर्ष में भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने पेट्रोलियम उत्पादों, हीरे को पछाड़



नई दिल्ली। पिछले तीन साल में भारत का स्मार्टफोन निर्यात पांच गुना हो गया है। वहीं इस दौरान जापान को निर्यात चार गुना हो गया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इस तरह स्मार्टफोन निर्यात ने देश से पेट्रोलियम उत्पादों और हीरे के निर्यात को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात 55 प्रतिशत के उछाल के साथ 24.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2023-24 में 15.57 अरब डॉलर और 2022-23 में 10.96 अरब डॉलर था। बीते वित्त वर्ष में अमेरिका, नीदरलैंड, इटली, जापान और चेक गणराज्य शीर्ष पांच देश रहे जहां स्मार्टफोन निर्यात में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज हुई है। अकेले अमेरिका को 2024-25 में स्मार्टफोन का निर्यात 10.6 अरब डॉलर का हो गया। - 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात 55 प्रतिशत के उछाल के साथ 24.14 अरब डॉलर पर अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात 2022-23 में 2.16 अरब डॉलर और 2023-24 में 5.57 अरब डॉलर रहा था। जापान को निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जापान को निर्यात 2022-23 के 12 करोड़ डॉलर से 2024-25 में 52 करोड़ डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड को निर्यात 2022-23 के 1.07 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 2.2 अरब डॉलर हो गया इसी तरह, इटली को निर्यात 72 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

अटारी-वाघा सीमा पर फिर से शुरू हुआ कारोबार

अटारी
जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था, लेकिन अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पुनः खुलने से व्यापारिक गतिविधियाँ फिर से चलने लगी हैं। इस सीमा के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला व्यापार फिर से गति पकड़ रहा है। पाकिस्तानी सीमा पर फंसे ट्रकों के विवाद के बाद अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके बाद लगभग 50 ट्रक और भारतीय ट्रकों ने सीमा पार करके व्यापारिक गतिविधियों को फिर से जीवंत किया। भारत और अफगानिस्तान के

पाकिस्तानी सीमा पर फंसे ट्रकों के विवाद के बाद भारत में प्रवेश की अनुमति मिली

बीच यह मार्ग सुखे मेवों और जड़ी-बूटियों के आयात के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बंद हो जाने से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। इस सीमा के खुलने से व्यापारियों में आर्थिक सुधार होने की उम्मीद है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार

जीईईएल ने अपनी ब्रांड पहचान को नया रूप देने की घोषणा की

नई दिल्ली। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईईएल) ने अपनी ब्रांड पहचान को नया रूप देते हुए अपने कॉर्पोरेट और चैनलों के लोगो को नया लुक देने की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ ने यह घोषणा जी सिने अवॉर्ड्स 2025 के दौरान की। नए लोगो जी टीवी, जी5, जी म्यूजिक कंपनी और जी स्टूडियोज जैसे ब्रांड्स के लिए जारी किए जाएंगे। नया कारपोरेट लोगो लॉन्च, बाकी ब्रांड्स के नए लोगो 8 जून को जारी किए जाएंगे कंपनी के अनुसार जी का नया कॉर्पोरेट लोगो पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, जबकि बाकी ब्रांड्स के नए लोगो 8 जून को जारी किए जाएंगे।

का यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। अटारी-वाघा सीमा भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच एकमात्र स्वीकृत व्यापारिक भूमि मार्ग है। भारत अफगानिस्तान से मुख्य रूप से सुखे मेवे और जड़ी-बूटियां आयात करता है, जो अधिकतर कंधार और काबुल से आते हैं। इस मार्ग के बंद होने से न केवल व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि बाजार में इन सामानों की उपलब्धता पर भी असर पड़ा।

वेदांता लिमिटेड : 20 अरब डॉलर की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कंपनियों की रुचि



नई दिल्ली
दुनिया की कई परामर्शक कंपनियों ने वेदांता लिमिटेड की कई क्षेत्रों में फैली 20 अरब डॉलर की विस्तार परियोजनाओं को लागू करने में रुचि दिखाई है। प्रमुख कंपनी चालू तिमाही में परामर्शक कंपनी का चयन करेगी। वेदांता अगले तीन साल में अपने परिचालन का महत्वपूर्ण विस्तार करने की योजना बना रही है, क्योंकि यह चार इकाइयों- वेदांता एल्युमीनियम, तेल और गैस, बिजली, और लौह एवं इस्पात में पुनर्गठन कर रही है।
वेदांता लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि वे एक वैश्विक रुचि पत्र जारी करेंगे और कुछ सप्ताह के भीतर भागीदार का चयन करेंगे। कंपनी अगले तीन साल में धातु, खनन, और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी। वेदांता के चेयरमैन ने इससे पहले कहा था कि कंपनी विविध कारोबार के विभाजन के बाद संपत्ति प्रबंधन से संपत्ति की मालिक बनेगी।
कंपनी अपने संपत्ति आधार को मजबूत कर रही है और वैश्विक अगुवा के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रही है। धातु क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की आमदनी 41,216 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें मार्च में समाप्त तिमाही में 3,483 करोड़ रुपये का आकलन शामिल है, जो पिछले साल की सामान्यतः 1,369 करोड़ रुपये से अधिक है।

ईबीपी मंच पर इलेक्ट्रॉनिक बुक व्यवस्था अनिवार्य
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निजी नियोजन के लिए ईबीपी मंच पर इलेक्ट्रॉनिक बुक व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान ईबीपी मंच की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। सेबी के नए परिपत्र के अनुसार, अब निजी नियोजन के लिए 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निगम आकार की ऋण या बॉन्ड प्रतिभूतियों, एनसीआरपीएस और म्युनिसिपल बॉन्ड जैसे अनुभागों के लिए भी ईबीपी मंच का उपयोग अनिवार्य होगा। अब तक निगम आकार वाले बॉन्ड प्रतिभूतियों के सभी निजी नियोजन के लिए ईबीपी मंच का प्रयोग अनिवार्य था, लेकिन अब रीट और इनविट भी इसमें शामिल होंगे। ईबीपी मंच की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने में मिलेगी मदद सेबी ने इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) और रियल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (आरईआईटी) को भी शामिल कर दिया है। इस पहल से इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदाता के मंच की महत्वपूर्णता और प्रभाव बढ़ेगा।



मूडीज ने घटाई अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग, निवेशकों को मिली चेतावनी, बढ़ सकती हैं ब्याज दरें

नई दिल्ली। मूडीज रेटिंग्स ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर एए1 कर दिया। यह पहली बार है जब मूडीज ने 1917 के बाद अमेरिका को परफेक्ट क्रेडिट स्कोर से वंचित किया है। इससे अमेरिकी निवेशकों को उधार लेने के लिए महंगा होने की संभावना है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव महंगाई और टैरिफ पर हो सकता है। मूडीज ने कहा कि पिछले दशक में अमेरिका का सरकारी कर्ज और ब्याज भुगतान का अनुपात बढ़ गया है, जो अन्य रेटिंग वाले देशों से अधिक है। एजेंसी का अनुमान है कि अमेरिका की उधारी की जरूरत और बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगी। रेटिंग को स्थिर आउटलुक दिया गया है, लेकिन फेडरल रिजर्व की नीतियां अब भी मजबूत और स्वतंत्र मानी जाती हैं। मूडीज के फैसले ने अमेरिका में राजनीतिक बहस को बढ़ावा दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने इसके लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वे कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन बाइडेन के गलत नीतियों को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं।



एजीआर मामला : सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया के बाद अब एयरटेल ने लगाई गुहार

भारती एयरटेल समूह पर 43,980 करोड़ की पर्याप्त एकमुश्त देनदारी लगाई गई

नई दिल्ली
वोडाफोन आइडिया के बाद अब भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया मामले में राहत की मांग कर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में कहा गया है कि एजीआर बकाया ने दोनों भारती कंपनियों की दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपने परिचालन को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया है।

यह हमारे भविष्य पर असर डाल सकता है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने एक दशक में लाइसेंस शुल्क और मुकदमे के जरिए लगभग 75,000 करोड़ रुपये का सरकारी खजाने में योगदान दिया है। इसके साथ ही जीएसटी भी दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 22,000 करोड़ रुपये था। एजीआर फैसले के जरिए भारती एयरटेल समूह पर 43,980 करोड़ रुपये की पर्याप्त एकमुश्त



देनदारी लगाई गई और इसे 31 मार्च, 2031 को समाप्त होने वाली 10 साल की अवधि के भीतर सरकार को चुकाया जाना है। मूल राशि 9,235 करोड़ रुपये ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज जोड़कर 43,980 करोड़ रुपये हो गई। इससे पहले गुरुवार को वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की, जिसमें

एजीआर बकाया से जुड़े ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की छूट की मांग की गई। करीब 20 करोड़ ग्राहकों को सेवा देने वाली इस दूरसंचार कंपनी ने राहत न मिलने पर वित्तीय संकट की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वोडाफोन आइडिया के मामले की सुनवाई करेगा।

अदित्य बिड़ला ग्रुप की एबीएलबीएल की शुरुआत 22 मई को

अदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने इस हफ्ते एक बड़ा ऐलान किया है कि उसकी कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड (एबीएलबीएल) की शुरुआत कर रही है। इस डिमर्जर के दौरान कंपनी का लाइफस्टाइल व्यवसाय अलग किया जाएगा और एक नई कंपनी का गठन किया जाएगा। नई कंपनी में मदुरा फैशन के प्रमुख ब्रांड्स शामिल होंगे। - नई कंपनी में मदुरा फैशन के प्रमुख ब्रांड्स शामिल होंगे डिमर्जर की रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट 22 मई गुरुवार को होगी, और निवेशकों को 1:1 के अनुपात में नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में 22 मई को तय होगा कि नई कंपनी के शेयर का शुरुआती भाव क्या होगा। इसके बाद लिस्टिंग डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। आदित्य बिरला फैशन के निवेशकों को अपने निवेश को बढ़ाने के लिए एक सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसमें कंपनी की महत्वपूर्ण ब्रांड्स के साथ जुड़ा है।

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वाहन पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी

टाटा मोटर्स ने 2024-25 में करीब 65,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे

नई दिल्ली
टाटा मोटर्स का लक्ष्य फरेलू यात्री वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को मुख्यधारा में लाने का है। अपनी इस योजना के तहत कंपनी ईवी श्रृंखला को मजबूत करने और साथ ही मौजूदा मॉडल के लिए मूल्य को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मुंबई की यह प्रमुख वाहन कंपनी चालू वित्त वर्ष में हैरियर ईवी और उसके बाद सिएरा ईवी उतारने की तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी अपने मौजूदा मॉडल में भी कई तरह के सुधार करने की योजना बना रही है। टाटा मोटर्स ने 2024-25 में करीब 65,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं। यह आंकड़ा 2023-24 की तुलना में 10 प्रतिशत कम है। तिमाही नतीजों के बाद निवेशक प्रस्तुतीकरण में कंपनी ने कहा कि हम नए मॉडल के साथ ईवी



पोर्टफोलियो को मजबूत करने जा रहे हैं। साथ ही मौजूदा मॉडल के लिए भी मूल्य बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी का इरादा इलेक्ट्रिक वाहनों के

मुख्यधारा में लाने है। इसके लिए कंपनी बाजार विकास और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी।

टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद
नई दिल्ली। भारत की डिजिटल सेवा कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक अपनी स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद जताई है। कंपनी के सीईओ ने बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क झटकों के बाद कंपनी की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। हैरिस ने बताया कि कंपनी ने पिछले 12 माह में व्यापार में नरमी का सामना किया उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया और उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि जैसे ही चीजें साफ होंगी, नए उत्पाद निवेश की मांग में वृद्धि को देखते हुए, हमें लगता है कि हम दूसरी तिमाही की शुरुआत में ही स्वस्थ वृद्धि दर्ज करेंगे। पहली तिमाही इन घोषणाओं से प्रभावित रहेगी और तथ्य यह है कि अमेरिका और विभिन्न भागीदारों के बीच बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को भरोसा है कि अमेरिकी व्यापार वार्ता को लेकर मई और जून में कुछ सफलता मिलेगी। इसे हमारे ग्राहकों के लिए उत्पाद निवेश निर्णय पर लौटने का रास्ता तैयार होगा।

